क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 341, गुरुवार, 10 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

रक्षामंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिले एचएएल के सीएमडी माधवन

नेशनल डेस्क। संसद भवन में बुधवार को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सीएमडी आर. माधवन ने रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। राफेल विवाद और एचएएल के वित्तीय संकट के बीच यह मुलाकात महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एचएएल के पास केवल तीन महीनों तक अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए थे। साथ ही एचएएल के सबसे बड़े ग्राहक भारतीय वायुसेना ने अपने बकाया नहीं चुकाए हैं। इससे पहले थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत, वायुसेनाध्यक्ष एयरचीफ मार्शल बीएस धनोआ और नेवी प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा संसद भवन पहुंचे थे। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है, जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को राफेल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के अधिकारियों की जानकारी के बगैर डील में बदलाव करके एचएएल की जगह अनिल अंबानी की कंपनी को फेंच कंपनी का ऑफसेट पार्टनर बना दिया। मोदी सरकार ने कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। अनिल और उनकी कंपनी भी आरोपों को नकार चुकी है।

ओबीसी में जातियां शामिल करने का मामलाः अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

नेशनल डेस्क। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूछा कि महाराष्ट्र सरकार ने कई जातियों को आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने के लिए 1967 में अधिसूचना जारी करने से पहले कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया था या नहीं। मुख्य न्यायाधीश एन एच पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की खंडपीठ सामाजिक कार्यकर्ता बीए सराटे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ओबीसी समूह में कई जातियों को शामिल करने को चुनौती दी गई थी। सराटे के वकील वी एम थोराट ने अदालत से कहा कि ओबीसी श्रेणी में शामिल 96 जातियों में से करीब 40 प्रतिशत आरक्षण के योग्य तक नहीं हैं। थोराट ने कहा कि इन जातियों को शामिल करना असंवैधानिक है। किसी जाति को आरक्षण के लिए किसी खास श्रेणी में शामिल करने के फैसले की एक तय प्रक्रिया है। सरकार इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। इसके बाद पीठ ने पूछा कि क्या सरकार ने किसी खास जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए 1967 में सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने से पहले कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया था या नहीं। याचिकाकर्ता ने 180 जातियों और उपजातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के जीआर को चुनौती दी है। इसके अलावा मार्च 1994 के उस सरकारी आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया गया था। मुख्य न्यायाधीश पाटिल ने कहा कि अध्ययन करने तथा डेटा एकत्रित करने के लिए एक पूरा आयोग होना चाहिए। याचिका में भी यह अनुरोध किया गया है।

आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश

आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश, कांग्रेस-सपा और मायावती ने किया समर्थन का ऐलान

नई दिल्ली।

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने से जुड़े 124वें संविधान संशोधन विधेयक को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन करने की घोषणा की है। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रो रामगोपाल यादव ने बुधवार को सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान इसका समर्थन करने का ऐलान किया। बसपा प्रमुख मायावती पहले ही बिल के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। भाजपा नेता थावरचंद गहलोत ने बिल को सदन में पेश करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक है। गहलोत ने कहा कि यह गरीबों के हित में है और केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच-विचार कर ही इस पर फैसला लिया है।

सदन की कार्रवाई पर एक नजर

- आनंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 में उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में यह मुद्दा शामिल था और कांग्रेस की ऐसी सोच भी रही है। पहले भी इसके लिए प्रयास किए गए और वर्ष 2006 में इसके लिए आयोग बनाया गया था। इसको लेकर कानून भी बनाए गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
- शर्मा ने कहा कि अब तीन राज्यों में मिली हार के बाद यह सरकार इस विधेयक को लेकर आई है और इसको लेकर राजनीति कर रही है।
- जिस तरह से इस विधेयक को लाने के लिए तेजी दिखाई गई है उसी तरह से महिला आरक्षण विधेयक में भी यह तेजी दिखाई जानी चाहिए।
- कांग्रेस सदस्य ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुअ कहा कि प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया गया था।
- युवाओं को सब्जबाग दिखाए गए थे लेकिन हकीकत में नौकरियां कम हुई है। वर्ष 2014 में केन्द्र के 34 लाख कर्मचारी थे और पिछले साढ़े चार वर्षों से अधिक समय में मात्र 95 हजार भर्तियां हुयी है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में 97 हजार नौकरियां कम हो गयी हैं।
- वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र में 11.85 लाख नौकरियां थी जो वर्ष 2017-18 में घटकर 10.88 लाख पर आ गई।
- शर्मा ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से निजी क्षेत्र में भी नौकरियां समाप्त हुई है। सबका साथ सबका विकास सोच अच्छा है लेकिन अच्छे दिन कब आएंगें। देश इसका इंतजार कर रहा है। सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारने, विकास को पटरी पर लाने का काम करना चाहिए लेकिन वह सपना दिखाने की फितरत में है।
- भाजपा के प्रभात झा ने सभी दलों के सदस्यों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस पहल से देश की 95फीसदी आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाएगी। मंडल आयोग ने भी इस संबंध में सिफारिश किया था और इससे हर भारतीय को लाभ होगा।

राज्यसभा में मोदी सरकार की स्थिति

लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत था लेकिन राज्यसभा में उसके पास अपने दम पर विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्याबल का अभाव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां सवाल उठा सकती हैं और बिल पर कड़ा रुख अपना सकती हैं। राज्यसभा में भाजपा के पास सबसे अधिक 73 सदस्य हैं, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के 50 सदस्य हैं। राज्यसभा में अभी सदस्यों की कुल संख्या 244 है। इतना संख्याबल होने के बावजूद भी भाजपा को बिल पास कराने के लिए विपक्ष के सहयोग की जरूरत है।

हालांकि कांग्रेस ने बिल पर समर्थन की बात कही है। राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत से काफी कम आंकड़ा है। के पक्ष में सिर्फ 90 सदस्य हैं।

ममता को झटका, टीएमसी सांसद सौमित्र खान भाजपा में हुए शामिल

नई दिल्ली।

लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता की अगुवाई की तैयारी में जुटी तृणमूल कांग्रेस को बुधवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उसके मौजूदा लोकसभा सांसद सौमित्र खान ने अपनी नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। खान बिष्णुपुर (सुरक्षित) सीट से सांसद हैं और वह 2014 में पहली बार संसद के लिए चुने गये थे। भाजपा के मुख्यालय में पार्टी महासचिव अरुण सिंह, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की मौजूदगी में श्री खान ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री मोदी एवं पार्टी अध्यक्ष शाह के नेतृत्व को स्वीकार कर भाजपा में शामिल होने के सांसद खान के निर्णय का पार्टी स्वागत करती है। उन्होंने कहा, ''हमें पूरा विश्वास है कि 2019 के अगामी लोकसभा चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भाजपा का पुनः उदय देश के पूर्वी क्षेत्र से होगा, जिसमें बंगाल व ओडिशा जैसे सभी पूर्वी राज्य बहुत अहम भूमिका निभाएंगे।'' खान ने कहा कि बंगाल के वरिष्ठ नेताओं का भाजपा में शामिल होना वहां की राजनीति की बदलती तस्वीर का सूचक है। युवाओं का भाजपा में शामिल होना, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में'सबका साथ,सबका विकास'की नीतिगत हो रहे समाज के समग्र विकास के प्रयासों की सफलता का अप्रतिम उदहारण है। आज के युवा श्री मोदी के नेतृत्व में देश के भविष्य को सुरक्षित एवं प्रगति की ओर अग्रसर देख पा रहे हैं।

फसल बीमा राफेल जैसा एक 'बड़ा' घोटालाःशिवसेना

बीड। एक पुस्तक का उद्धरण देते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि केन्द्र की फसल बीमा योजना 'उसी तरह का एक बड़ा घोटाला' है जैसा राफेल लड़ाकू विमान सौदा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अक्सर होने वाले विदेशी दौरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केवल भाषणों और घोषणाओं से लोगों की मदद नहीं होगी। उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली सरकार से आगामी चुनावों के लिए गठबंधन पर बातचीत पर विचार से पहले किसानों की समस्याओं को सुलझाने की मांग की। मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोग के कारण अधिसूचित फसलों में से किसी के नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहयोग मुहैया कराना था। सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान महाराष्ट्र के बीड जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि बीमा कंपनियों को किस्तों का भुगतान करने के बाद सरकार की फसल बीमा योजना का कितने लोगों को लाभ मिला? उन्होंने कहा,'लोगों को दो, पांच, 50, 100 रुपए का चेक मिला। मैं मन की बात नहीं करता (मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम का हवाला देते हुए) लेकिन 'जन की बात' करने में विश्वास करता हूं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि फसल बीमा योजना में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है।' ठाकरे ने कहा, 'हमें किससे सवाल करना चाहिए? साईनाथ नाम का कोई है, जो इस विषय का विशेषज्ञ है जिसने एक किताब लिखा है। उन्होंने कहा है कि फसल बीमा घोटाला राफेल के जैसा एक बड़ा घोटाला है।'

अयोध्या विवादः सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आज राम मंदिर पर करेंगे सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक संबंधी विवाद पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी। इस 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन मंगलवार को किया गया। यह पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस उदय यू. ललित और जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ शामिल हैं। पिछले शक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान गोगोई ने कहा था कि यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है, लिहाजा तीन जजों की बेंच सुनवाई नहीं करेगी। पिछली सुनवाई में महज 30 सेकंड में कोर्ट ने यह कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। कोर्ट की कार्रवाई मात्र एक मिनट तक ही चली और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी बहस नहीं हुई। अब एक बार फिर से लोगों की नजरें गुरुवार को आने वाले फैसले पर होंगी।

जनता की अदालत

जनता की अदालत से भाग गया 56 इंच की छाती वाला चौकीदारः राहुल गांधी

जयपुर।

राफेल विमान सौदे पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर हाजिरी पर वार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि ''छप्पन इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में कदम नहीं रख पाए।'' उन्होंने कहा कि जब जनता की अदालत, लोकसभा में राफेल मामले पर चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में एक विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे थे।

राहुल ने कहा, ''चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डरकर भाग गया। छप्पन इंच की छाती वाला चौकीदार जनता की अदालत से भाग गया।'' इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की कर्जमाफी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है और इसके अन्य स्थाई विकल्पों पर विचार करना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने पर मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ही मालिक है और हम यहां सेवा करने आए हैं। राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं का आरोप दोहराते हुए राहुल ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए तथा संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बननी चाहिए। राहुल ने कहा, ''कांग्रेस ने राफेल सौदे पर जनता की अदालत में सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी जी आप सामने आइए। राफेल मामले में कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी और आप अपनी बात रखिए।

आपने देखा होगा कि छप्पन ईंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में एक मिनट के लिए भी नहीं आ पाए। ढाई घंटे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण दिया। वह हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाईं। लेकिन मोदी ने एक मिनट के लिए लोकसभा में अपना चेहरा नहीं दिखाया।'' राहुल ने कहा, '' लोकसभा में राफेल मामले पर चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए और वहां की एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं। मगर जनता की अदालत में, मोदी जी ने एक मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा। चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डरकर भाग गया।

जनता की अदालत से छप्पन इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया। और एक महिला से कहता है... कि सीतारमण जी से कहता है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाउंगा।

ढाई घंटे वह महिला रक्षा नहीं कर पाईं।'' इसके साथ ही राहुल ने कहा कि रक्षा मंत्री सीतारमण ढाई घंटे बोलने के बावजूद कांग्रेस के सीधे साधे सवाल का हां या ना में जवाब नहीं दे पाईं।

आर्थिक आधार पर आरक्षण को कांग्रेस ने बताया राजनीति से प्रेरित कदम

नई दिल्ली।

सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बुधवार को हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसके लाए जाने के समय पर सवाल किया और आरोप लगाया कि यह राजनीति से प्रेरित कदम है। सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने संविधान (124वां) संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए सवाल किया कि ऐसी क्या बात हुई कि यह विधेयक अभी लाना पड़ा? उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। शर्मा ने कहा कि इन विधानसभा चुनावों में हार के बाद संदेश मिला कि वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब अपने कार्यकाल के आखिरी चरण (डिपार्चर लाउंज) में है, तब उसने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार चार साल सात महीने बाद यह विधेयक लेकर आयी है। यह इस आखिरी सत्र है और उसके बाद चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता भोली और सज्जन है तथा वह आशीर्वाद भी देती है लेकिन वह मूर्ख नहीं है। जनता एक बार वादों में भले ही बहक जाए लेकिन उसे हिसाब देने का समय भी आ रहा है। शर्मा ने आरक्षण के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के चुनाव में कई सब्जबाग दिखाए गए और लोगों से बड़े बड़े वायदे किए गए। उन्होंने सरकार पर युवाओं एवं किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे पहले अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल रोजगार के दो करोड़ मौके सृजित करने की बात कर रही थी लेकिन वास्तव में इसका उलटा हुआ। शर्मा ने कहा कि सरकार के विभिन्न कदमों से न सिर्फ रोजगार के मौके कम हो गए वहीं अर्थव्यवस्था को भी भारी झटका लगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार को महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के बारे में भी विचार करना चाहिए।

तृणमूल की 19 जनवरी की रैली में हिस्सा नहीं लेंगे वामदल : भाकपा महासचिव

हैदराबाद।

भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने बुधवार को कहा कि वाम दल 19 जनवरी को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्ष की रैली में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के साथ कटु संबंध हैं। ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विपक्षी दलों की रैली बुलाई है। रेड्डी ने कहा,'चूंकि हमारे संबंध पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ कटु हैं, इसलिए वाम दल उस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।' उन्होंने कहा,'हमने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।'भाकपा नेता ने कहा, 'अगर अन्य पार्टियां हिस्सा लेना चाहती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है तो हम राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह के (विपक्षी पार्टियों के) संयुक्त मंच के लिये तैयार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर हम यह नहीं कर सकते।' इस बीच, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को 'चुनावी जुमला' करार देते हुए रेड्डी ने कहा कि यह कदम कई अप्रत्याशित समस्याओं को जन्म देगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार गंभीर थी तो उसे सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, न कि किसी एक पार्टी का। भाकपा महासचिव ने कहा,'एकबार 10 फीसदी दिया गया तो कई अगड़ी जातियां इससे संतुष्ट नहीं होंगी। वो और मांग करेंगी। अंततः कोई आरक्षण नहीं होगा।'उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन आरक्षण का पैमाना है।

संपादकीय

पीएम के साक्षात्कार पर विवाद अनुचित

साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मीडिया संस्थान को दिए साक्षात्कार के बाद तरह-तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। सवाल ऐसे भी उठाए जा रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री की किसी भी पत्रकार वार्ता या साक्षात्कार का जैसा स्वरूप हमें पहले देखने को मिल चुका है, वैसा ही मोदी के साथ भी दिखा। अतः अब इस पर विवाद अनुचित है।

वर्ष 2019 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि एक एजेंसी को 95 मिनट का लंबा साक्षात्कार देते हैं तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिक उद्देश्य होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री यदि देश के नाम संदेश देते तो वह भी इसी तरह सभी चैनलों पर लाइव दिखाया जाता और चैनलों पर बहस के अलावा समाचार पत्र-पत्रिकाओं और वेबसाइटों पर भी उस पर टिप्पणियां आतीं। जाहिर है, प्रधानमंत्री मोदी भाषण की जगह साक्षात्कार के रूप में ही अपनी बात कहना चाहते थे। एजेंसी को साक्षात्कार देने का हेतु यही था कि वह सभी चैनलों पर चले। इसमें उन्होंने लगभग उन प्रश्नों का तो उत्तर दिया ही जो विपक्ष की ओर से उन पर एवं उनकी सरकार पर उठाए जाते रहे हैं, अपने संगठन परिवार को भी अयोध्या में राममंदिर मुद्दे पर संकेत देने की कोशिश की। इसमें बहुत सारे प्रश्न और उत्तर वही थे जो हम प्रधानमंत्री के मुंह से पहले भी सुन चुके हैं। बावजूद इसके देश के सामने एक साथ उन सबको रखना राजनीति के लिए जरूरी था। किंतु इस समय पूरे साक्षात्कार को ही विवादास्पद और स्टेज मैनेज्ड बताने की मुहिम चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साक्षाकार लेने वाली पत्रकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उसे अंग्रेजी में प्लायबल यानी आज्ञाकारी तक करार दे दिया। राहुल ने यह भी कह दिया कि वो प्रश्न पूछ रही थीं और जवाब भी स्वयं दे रही थीं।

यह ठीक है कि कई जगह पत्रकार को जितनी मर्यादित आक्रामकता प्रदर्शित करनी चाहिए थी उतनी वह नहीं कर पाईं। कई काउंटर प्रश्न पूछे जा सकते थे जो उन्होंने नहीं पूछा। किंतु हर पत्रकार का अपना तरीका होता है। वैसे आलोचकों को कुछ बातें पता जरूर होनी चाहिए। पहले की सरकारों में भी आप किसी मंत्री से साक्षात्कार के लिए समय मांगते तो उनके सहायक का फोन आ जाता था कि प्रश्न बनाकर मेल कर दीजिए। इस सरकार में भी कुछ मंत्री ऐसा करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो साक्षात्कार उस दौरान दिए उसमें भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि ऐसे कुछ पत्रकार तब भी थे और आज भी हैं जो साक्षात्कार के बीच कुछ प्रतिप्रश्न या दूसरे प्रश्न भी पूछ लेते थे और पूछते हैं। सोनिया गांधी के दो साक्षात्कार मुझे याद हैं जिनमें राजनीति और सरकार पर कोई प्रश्न पूछा नहीं गया। उनसे सास इंदिरा गाधी से संबंधों, उनके खानपान, परिवार के रिश्ते जैसे प्रश्न ही पूछे गए। सरकार के किसी निर्णय या अन्य घटना पर साक्षात्कार या पत्रकार वार्ता की जगह उनका बयान आ जाता था और वह मीडिया की सुर्खियां बनता था। पूरे दस वर्ष ऐसे ही चला। सोनिया गांधी की चर्चा इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थीं जिनके सुझाव यूपीए सरकार के लिए आदेश के समान होते थे। पीएम न होते हुए भी वो सुपर प्रधानमंत्री की भूमिका में थीं। राहुल के एक साक्षात्कार में तो उनके पेट का हालचाल तथा खानपान तक पूछा गया। तब उन पत्रकारों पर कोई प्रश्न नहीं उठा।

मनमोहन सिंह की हर पत्रकार वार्ता के पहले मीडिया संस्थानों से पत्रकारों के और उनके प्रश्न मंगाए जाते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय उन प्रश्नों में से चयन करता था और उनके अनुसर पत्रकारों का क्रम निर्धारित होता था। पत्रकार का नाम लिया जाता था और उसके अनुसार प्रश्न आता था। हालांकि दो-चार अतिरिक्त प्रश्न भी हो जाते थे। या कोई पत्रकार अपने मूल प्रश्न में एकाध प्रश्न जोड़ देता था। हमने ऐसे दृश्य देखे जब एकाध असुविधाजनक प्रश्न पर मनमोहन सिंह को कठिनाई हुई तो उनके साथ बैठे मीडिया सलाहकार या दूसरे अधिकारी ने इस पर नाखुशी जाहिर की और प्रश्न को टालकर दूसरे का नाम ले लिया। मोदी सरकार में भी कई मंत्रियों की पत्रकार वार्ता में नाम और प्रश्न मांग लिए जाते हैं। हां, मंत्री जी की कृपा से कुछ ऐसे पत्रकारों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति मिल जाती है जो सूची में नहीं है। यह एक विकृत और अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। किंतु इसके विरोध में मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों को ही खड़ा होना पड़ेगा। क्या हम ये नहीं कह सकते कि पत्रकार वार्ता करनी है तो हमें प्रश्न पूछने की पूरी आजादी होनी चाहिए?

इस समय ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो मोदी के साथ सब कुछ पूर्व लिखित पटकथा के अनुसार ही मंचित होता है। यह गलत आरोप है। मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कई साक्षात्कार दिए हैं जिनमें ऐसे प्रश्न भी पूछे गए जो वाकई पत्रकार के मन से तत्क्षण निकले थे। अधिकतर टीवी संस्थानों से लेकर प्रिंट के प्रमुख अखबारों से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कई अखबारों को ईमेल प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हम यह मान लें कि जिनने मोदी का साक्षात्कार लिया सब सत्ता के सामने झुके हुए या मोदी की चापलूसी करने वाले पत्रकार थे तो इसका कोई तार्किक जवाब देने की आवश्यकता नहीं। किसी पत्रकार का नाम लेना कतई उचित नहीं, अन्यथा इनका भी सप्रमाण चरित्र चित्रण किया जा सकता है। मोदी का तरीका यह है कि वो पत्रकार के साथ साक्षात्कार लेने के पहले औपचारिक नहीं रहते जैसे मनमोहन सिंह रहते थे। बातचीत कर पत्रकार को सहज संबंध की अवस्था में ले आते हैं। पहले उनका हालचाल पूछते हैं, कुछ समस्यायें हैं तो उनकी जानकारी लेते हैं। इसका असर पत्रकार पर होता है। वर्तमान साक्षात्कार को लेकर इतना नकारात्मक व विवाद का माहौल केवल मोदी के प्रति व्याप्त घृणा की परिणति है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जवाबों से सहमति-असहमति हो सकती है जिसे प्रकट करने का सबको अधिकार है। उसका तार्किक व तथ्यात्मक विरोध करने तो कोई समस्या ही नहीं है। पर मोदी साक्षात्कार दें, कोई वक्तव्य दें वो सब केवल अभिनय है, जिस पत्रकार को साक्षात्कार का अवसर मिल गया वह गिरा और बिका हुआ है ऐसी ओछी मानसिकता रखने से हम कभी निष्पक्ष आकलन नहीं कर सकते। ऐसा करने वाले हैं कौन उनके चेहरे देखिए, थोड़ी पृष्ठभूमि खंगालिए, सच सामने आ जाएगा।

मोदी या किसी भी मंत्री या नेता को इतना अधिकार मिलना चाहिए कि अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं तो वो इसका चयन करें कि किस संस्था और पत्रकार से करेंगे। ऐसा पहले से होता रहा है। मूल बात होती है उसमें उन्होंने कहा क्या। इस साक्षात्कार में मुख्यतः चार बातों पर देश को कुछ नया सुनने को मिला- सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, रिजर्व बैंक के गवर्नर का इस्तीफा एवं राममंदिर निर्माण। सर्जिकल स्ट्राइक की जो विस्तृत कथा बताई उसमें कुछ अंश नए थे और यह देश को जानना जरूरी था। नोटबंदी को भी उन्होंने झटका न मानकर इसका थोड़ा नया विश्लेषण किया। इसी तरह उर्जित पटेल के इस्तीफा पर उन्होंने कहा कि वो छह महीना पहले से उनसे मुक्त करने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। इस पर यकीनन काउंटर प्रश्न बनता था। किंतु पत्रकार नहीं पूछ पाई तो यह उनकी कमजोरी हो सकती है, इसके लिए उसे बिका हुआ कहना उचित नहीं।

सबसे महत्वपूर्ण बात मंदिर निर्माण पर थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सरकार कदम उठा सकती है। साक्षात्कार से यह तो सामने आया कि प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं लेकिन वो न्यायालय का सम्मान बचाए रखकर ही कदम उठाना चाहते हैं। हालांकि भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तन को संसद में पलटना बना है। इस विषय पर कुछ सामने आया ही नहीं। इन पर बहस करने की जगह साक्षात्कार को नाटक और पत्रकार को उसका पात्र बनाने वाले अपने को ही छोटा साबित कर रहे हैं। कौन पत्रकार है जिसे प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बात करने के लिए बुलाए और वह तैयार नहीं होगा?

अवधेश कुमार
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

गरीब सवर्णों को आरक्षण जरूरी

मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सौगात दी है। फैसला देखने में अभी भले ही राजनीतिक लगे मगर इस फैसले को सामाजिकता के दायरे में रखना ज्यादा मुफीद होगा। देखना है कि सवर्णों को इससे कितना फायदा होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। लंबे समय से गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग उठती रही है और अब मोदी सरकार ने इस मांग को पूरा करना बड़ा कदम माना जा रहा है। यह आम धारणा है कि सवर्ण का मतलब होता है समर्थ लेकिन यह सही नहीं है। सवर्णों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। यह आंकड़ों से भी साबित हो चुका है। इसके मद्देनजर आरक्षण उनकी जायज मांग है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से कृषि क्षेत्र और किसानों की हालत खराब हुई है। फसल उगाने के लिए पहले से ज्यादा निवेश करना पड़ रहा है जबकि उससे बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। इससे न सिर्फ सवर्ण बल्कि अन्य जातियां भी प्रभावित हुई हैं लेकिन आरक्षण के कारण अन्य जातियों को इससे बचने में मदद मिली है जबकि आर्थिक रूप से सवर्ण के पास कोई चारा नहीं है। फिर शहरी इलाकों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण भी लोगों में असंतोष है। खासकर निजी क्षेत्र में पहले कम नौकरियां हैं।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की बात है तो वहां आरक्षण के कारण सवर्णों के लिए बहुत कम मौके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के महसूस हो रहा है कि बिना आरक्षण के उनका कल्याण संभव नहीं है क्योंकि अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोग आरक्षण का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी वे मजबूत हुए हैं। सवर्णों को आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है और इसे राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त है। दरअसल, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो इसका विरोध करने का साहस कर सके। यहां तक कि दलित हितों के प्रति चिंतित रहने वाली बसपा जैसी पार्टी भी सवर्णों के लिए आरक्षण की वकालत कर चुकी है। बसपा ही वह पार्टी है, जिसने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर अगर-मगर के साथ सबसे पहले सहमति जताई। उसके बाद तो कई क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर सहमति जताती नजर आने लगीं। मोदी सरकार के इस फैसले में इसी साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में फायदा लेने की सोच भले ही निहित हो, मगर सच यह भी है कि फैसला गरीबों के जीवन को बेहतर बनाएगा।

अगर इस फैसले को राजनीति के चश्मे से देखें तो यह सभी को पता है कि एससी-एसटी एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन से अगड़ी जातियां नाराज हैं। इस नाराजगी से भाजपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार झेलनी पड़ी। इन राज्यों में जहां सवर्णों के पास विकल्प थे, वहां इस वर्ग ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और जहां नहीं था, वहां नोटा का इस्तेमाल किया। तीन राज्यों में करीब 12 लाख वोट नोटा में पड़े। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि ये वोट भाजपा से नाराज सवर्णों के थे। अतः उन्हें साधना बेहद जरूरी था।

विकास में भागीदार बनें प्रवासी

आज भारतीय प्रवासी दिवस है। इस दिन का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों से संपर्क के जरिए देशों से संबंध मजबूत बनाना है। विश्व के कोने-कोने में रहने वाले भारतीयों से ही पूरे विश्व में भारत का दिल धड़कता है। हालांकि, अब भी प्रवासियों के लिए काफी कुछ काम किया जाना बाकी है। खासकर खाड़ी देशों में काम करने वालों के लिए। सरकार को चाहिए कि वह विदेशों में बसे भारतीयों की सभी मुश्किलों को हल करे।

दुनिया के कोने-कोने में बसे प्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अप्रवासी नागरिक किसी भी देश के विकास का एक आधार स्तंभ होते हैं। वे दुनिया को उस देश से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया होते हैं और भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो उसके भारतवंशी प्रवासी नागरिक अमूल्य निधि की तरह हैं, जिनका देश के विकास में हमेशा से सकारात्मक योगदान होता है। प्रवासी भारतीय दिवस सरकार द्वारा प्रतिवर्ष नौ जनवरी को मनाया जाता है। नौ जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और अंततः दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों और औपनिवेशिक शासन के तहत लोगों के लिए और भारत के सफल स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा बने। यह दिन हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।

इस परंपरा की शुरुआत 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉ. लक्ष्मीमल सिंधवी के प्रयासों से हुई थी। तब से लेकर आज तक यह जारी है। बीच के कुछ वर्षों में आयोजन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया था। राजग सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को प्रेमोन्मुख बनाया था, लेकिन संप्रग सरकार ने मायने ही बदल डाले थे। उसने इसे महज रस्म अदायगी का विषय बनाते हुए लाभ उन्मुख बना दिया। संप्रग सरकार की नजरें केवल उन प्रवासियों पर रहती थीं जो कि विदेशों में अच्छी धाक जमा चुके हैं और उन लोगों को नजरअंदाज करती रही है जो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं खाड़ी के देशों में अब भी निचले स्तर पर जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर से इसे अपने मूल ढर्रे पर ला खड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल डॉलर और पाउंड की आमद के उद्देश्य से नहीं किया जाता अपितु अपने जनों के दिलों के मेल के लिए किया जाता है।

आज के समय में विश्व के सौ से अधिक देशों में बसे प्रवासी भारतीयों की संख्या 2.75 करोड़ आंकी गई है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व का हर छठा प्रवासी भारतीय है। कई देशों में तो प्रवासी भारतीय वहां की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ वहां की आर्थिक व राजनीतिक दशा दिशा को भी तय करते हैं। जहां भी भारतीय गए वहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वे शिक्षक, व्यापारी, चिकित्सक, अधिवक्ता यहां तक की अभियंता, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, शासक एवं प्रशासक आदि के रूप में भी स्वीकार किए गए। विदेशी आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान करने में भी भारतीय पीछे नहीं हैं। कुछ देशों में तो वहां की राष्ट्रीय आय में एक बड़ा हिस्सा प्रवासी भारतीयों का ही होता है। भारतवंशियों की इन्हीं सफलताओं के चलते भारत की छवि में दिन-ब-दिन निखार आ रहा है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि प्रवासी भारतीयों के सशक्त एवं प्रभावी होने के बाद भी भारत के विकास में योगदान देने से हिचकिचाते क्यों हैं? वे चीनी प्रवासियों की तरह अपने मूल देश की तरक्की में पीछे क्यों हैं?

एक अनुमान के मुताबिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवासी भारतीयों का हिस्सा महज छह फीसदी है, जो कि चीन के मुकालबे बहुत कम है। एक सर्वे के मुताबिक चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवासी चीनियों का 67 फीसदी हिस्सा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या प्रवासी भारतीयों को अपने मूल देश से प्रवासी चीनियों के मुकाबले कम लगाव है? क्या वे मातृभूमि के प्रति अपने फर्ज को भूल गए हैं? यदि प्रवासियों के भारत के प्रति उदासीनता के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो मालूम चलता है कि कमी उनके चरित्र में नहीं अपितु हमारे राष्ट्रीय चरित्र में ही है। प्रवासी भारतीयों के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। एक भारतीय चाहे वह देश में रहता हो या विदेश में अपने देश से समान लगाव रखता है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवासी भारतीयों की कम भागीदारी के लिए हमारी सरकारी नीतियां ही सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सरकार की नीतियों का निष्पक्ष व ईमानदारी से आकलन करने से पता चलता है कि हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं जितना कि हम सोचते हैं। निवेश वहीं होता है जहां पर लाभ की गुंजाइश होती है। यही कारण है कि अनिवासी भारतीय तो दूर निवासी भारतीय भी भारत में निवेश से कतराते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से भारत के सभी बड़े औद्योगिक घराने विदेश में निवेश को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उनके टर्न ओवर का बड़ा हिस्सा विदेश में किए गए निवेश से आ रहा है। अब सरकार मौजूदा आर्थिक विपदा को एक अवसर में तब्दील करने का अगर संकल्प लेती है तो इससे प्रवासी एवं अप्रवासी दोनों को लाभ मिलेगा।

एक बात और जो हमारे मन में उठ रही है वह यह है कि क्या हम अपने प्रवासी भाई-बंधुओं से अपना अधिक से अधिक आर्थिक हित साधने के लिए उनसे नाता रखना चाहते हैं? हमें यह याद रखना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। प्रवासी भारतीयों से परस्पर ज्ञान व विज्ञान के विनिमय से भी भारत विकास के पथ पर तेजी से दौड़ सकता है। अब इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रवासी भारतीयों ने अपनी प्रतिभा का झंडा पूरी दुनिया में फहरा रखा है। रिपोर्ट के अनुसार नासा में कार्यरत 36 प्रतिशत वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। 38 प्रतिशत डॉक्टर भारतीय हैं। माइक्रोसाफ्ट में काम करने वाले 34 प्रतिशत, आईबीएम में 28 प्रतिशत एवं इंटेल में 17 प्रतिशत भारतीय ही हैं। स्वदेश पैसा भेजने के मामले में भी भारतीय पहले नम्बर पर हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि विगत वित्त वर्ष के दौरान भारतीयों ने अपने देश को कुल 56 अरब डॉलर की राशि भेजी है। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की है लेकिन सुविधाओं के अभाव में अभी तक इसके द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए काई कारगर पहल नहीं की गई। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने का वादा भी अभी जस का तस है। मत देने का अधिकार जरूर दे दिया गया है लेकिन यह नाकाफी है।

यदि प्रवासियों से किए गए वादों पर नजर डाली जाए तो एक लंबी फेहरिस्त नजर आती है। अब वादों की फेहरिस्त लंबी करने की बजाए पूरा करने पर जोर दिया जाए तो निश्चय ही आने वाले समय में देश को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही प्रवासियों को अपनी जड़ों को जानना चाहिए साथ ही अपने पिता एवं पूर्वजों के अतीत के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। प्रवासी भारत के सॉफ्ट पॉवर का अहम उदाहरण हैं। एक दशक पहले प्रवासी भारतीयों का सम्मलेन एक खास मकसद से शुरू किया गया था, वह था विदेशों में बसे भारतीयों को अपने देश से जोड़ना और उनकी मदद से देश में निवेश को बढ़ावा देना। प्रवासी दिवस पर पूर्व में किए गए सम्मेलन अपने मकसद में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब भी निवेश प्रोत्साहन के लिए बहुत काम किया जाना शेष है। साथ ही विदेशों में खासकर खाड़ी देशों में बसे भारतीयों की कठिनाइयों को कम करने की दिशा में भी काम करने की जरूरत है।

इस समय में पूरा विश्व भारत को अपरिमित उम्मीद और आशा से देख रहा है। अमीर और गरीब दोनों ही देश भारत की तरफ देख रहे हैं। समय बहुत तेजी से बदला है। ऐसे में यह भारत से बाहर बसे भारतवंशियों की जिम्मेदारी है कि वे इस अवसर का इस्तेमाल मानवता के कल्याण के लिए करें।

सुनील तिवारी
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

पीएम मोदी की नीतियों ने हमेशा देश में गरीबों के उत्थान में मदद की है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण इसी सोच को इंगित करता है।

अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

ओबीसी के लिए भी आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए था, सरकार लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है। आरक्षण के प्रस्ताव का उनकी पार्टी समर्थन करती है।

रामगोपाल यादव, सपा नेता

सत्यार्थ

असली मूर्ख कौन?

एक बार एक मजदूर अपने गधे के साथ जंगल से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान उसे रास्ते में पड़ा एक चमकीला पत्थर दिखा। उसे वह पत्थर अच्छा लगा। उसने उसे उठाया और अपने गधे के गले में लटका दिया। वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सामने से एक जौहरी आया। जौहरी ने बेशकीमती पत्थर देख मजदूर से पूछा- भैया, मैं यह पत्थर खरीदना चाहता हूं। बोलो इसके कितने पैसे लोगे? मजदूर को उस पत्थर की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने कहा कि वह पत्थर के सौ रुपए लेगा। जौहरी ने कहा- सौ रुपए तो ज्यादा हैं। मैं इसके 50 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। जौहरी यह सोचकर आगे बढ़ गया कि इसे इस पत्थर का कोई और ग्राहक तो मिलेगा नहीं, सो थोड़ी देर में वह खुद 50 रुपए में पत्थर देने वापस आ जाएगा, पर मजदूर आगे बढ़ा तो उसे एक और जौहरी मिला। उसने भी कीमती पत्थर को फौरन पहचान लिया और मजदूर से पूछा- भैया, अपने गधे के गले में बंधा हुआ यह पत्थर बेचोगे? इस बार मजदूर कुछ चौंका और उसने पत्थर के दो सौ रुपए मांग लिए। दूसरे जौहरी ने फौरन दो सौ रुपए देकर पत्थर ले लिया। तब तक पहले वाले जौहरी को चिंता हुई और वह भागता हुआ वापस आया कि चलो पत्थर खरीद ही लूं। यहां आने पर जब उसे पता चला कि मजदूर ने दो सौ रुपए में पत्थर बेच दिया, तो खीझकर बोला-अरे मूर्ख वह दो सौ रुपए का मामूली पत्थर नहीं, लाखों रुपए का बेशकीमती पत्थर था। मजदूर बोला- मूर्ख मैं नहीं, आप हैं। मैं तो पत्थर की असली कीमत नहीं जानता था, इसलिए उसे दो सौ रुपए में बेचा, पर आप तो उसकी असली कीमत जानते हुए भी 50 रुपए के लालच में उससे वंचित रह गए हैं।

आशा गुप्ता

एएफसी एशियन कप

यूएई को हराकर इतिहास रचना चाहेगी भारतीय टीम

अबू धाबी ।

एएफसी एशियन कप के पहले मैच में थाईलैंड के खिलाफ 4-1 से धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय फुटबाल टीम गुरुवार को यहां जायेद स्पोर्ट्स सिटी में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट के नॉकआउट स्तर में पहुंचना चाहेगी। थाईलैंड के खिलाफ मिली बड़ी जीत से भारत तीन अंक प्राप्त हुए और वह अब अपने ग्रुप में टॉप पर है। भारतीय टीम का गोल अंतर भी बेहतर है जो ग्रुप स्तर पर महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि यूएई ने अपने पहले मैच में बहतरीन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था। कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन इस बात को लेकर खुश होंगे कि उनके खिलाड़ियों ने थाईलैंड के खिलाफ दूसरे हाफ में बेहतरीन खेल दिखाया। पहला हाफ 1-1 की बराबरी पर समाप्त होने के बाद भारत ने न सिर्फ मजबूत थाई डिफेंस को तोड़ने में सफलता हासिल की बल्कि उसने कई बेहतरीन गोल करते हुए इस मैच को अपने लिए यादगार बना दिया। कांस्टेनटाइन ने कहा, हमारी टीम काफी युवा है और इस कारण वह काफी रोमांचित है। मेजबान टीम के साथ होने वाला मैच काफी अलग होगा क्योंकि यह टीम काफी मजबूत है लेकिन मेरे लड़कों के लिए यूएई उनके रास्ते में खड़ी सिर्फ एक अन्य टीम है।÷ भारत ने अपने फारवर्ड खिलाड़ियों के शानदार खेल की बदौलत थाईलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। सुनील छेत्री ने दो गोल और जेजे लालपेखलुवा ने एक गोल किया जबकि मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला गोल करने में सफल रहे। आशिक कुरुनियन इस मैच में कोई गोल नहीं कर सके लेकिन उन्होंने अपने शानदार खेल से सबका ध्यान खींचा। छेत्री और एफसी पुणे सिटी के विंगर कुरुनियन ने थाईलैंड की रक्षापंक्ति को हमेशा व्यस्त रखा। कुरुनियन से यूएई के खिलाफ भी इसी तरह के चमकदार खेल की उम्मीद है। यूएई फीफा रैंकिंग में 79वें स्थान पर है और भारत से काफी बेहतर स्थिति में है। ग्रुप-ए में वह सबसे ऊंची रैंकिंग वाला टीम है और यह भारत के लिए एक चिंता की बात है। एक मजबूत टीम के खिलाफ मिडफील्ड में थापा और प्रणॉय हल्धर को अच्छा खेल दिखाना होगा। भारत को पीछे की पंक्ति में भी काफी सावधान रहना होगा क्योंकि 2015 में एशियन प्लेअर ऑफ द इअर चुने गए अहमद खलील और अली मबखाउत जैसे खिलाड़ी उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ये खिलाड़ी गोल करने में माहिर हैं। मबखाउत को यूएई के लिए सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बनने के लिए सात गोलों की जरूरत है। ऐसे में संदेश झिंगन और अनस इडाथोडिका को बैकलाइन में काफी सतर्क रहना होगा। यूएई घरेलू दर्शकों के सामने पहले मैच में पूरे तीन अंक हासिल न कर पाने के कारण घायल दिख रही है और उनके कोच ने भी माना कि भारत के खिलाफ वे बदली हुई मानसिकता के साथ उतरेंगी। यूएई के कोच अल्बटरे जाचेरोनी ने कहा, हमारे खिलाड़ी पहले मैच में अपनी संघर्षशक्ति नहीं दिखा सके थे। हम भारत के खिलाफ यह गलती नहीं करेंगे। हम बदली हुई मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेंगे। यूएई की टीम को चोटिल ओमर अब्दुलरहमान की कमी खलेगी। ओमर को एशिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक माना जाता है लेकिन जाचेरोनी की टीम को पास ओमर के बगैर भी काफी शक्ति और काबिलियत है और इस कारण गोलपोस्ट के सामने गुरप्रीत सिंह संधू को काफी सावधान रहने की जरूरत होगी। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, विशाल कैथ। डिफेंडर प्रीतम कोटाल, संदेश झिंगन, अनस एदाथोडिका, सलाम रंजन सिंह, सार्थक गोलुई, सुभाशीष बोस । मिडफील्डर = उदांता सिंह, जैकीचंद सिंह, प्रणॉय हल्दर, अनिरुद्ध थापा, विनीत राय, रॉलिंग बोर्गेस, जर्मनप्रीत सिंह, अशिक कुरुनियान, हालीचरण नारजारे। फारवर्ड = सुनील छेत्री, जेजे लालपेखलुआ, बलवंत सिंह, सुमित पस्सी।

ईएफएल कप : टोटेनहम हॉटस्पर ने चेल्सी को 1-0 से मात दी

लंदन । टोटेनहम हॉटस्पर ने मंगलवार रात यहां ईएफएल कप के सेमीफाइनल के पहले लेग में चिर-प्रतिद्वंद्वी चेल्सी को 1-0 से मात दी। इस सेमीफाइनल मुकाबले का दूसरा लेग 22 जनवरी को खेला जाएगा। वेम्बली स्टेडियम में खेले गए इस मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली लेकिन चेल्सी को एक स्ट्राइकर की कमी खली। चेल्सी के मुख्य कोच मॉरिजियो सारी ने इस मैच के शुरुआती 11 में ओलिवर जिरू को शामिल नहीं किया जबकि अल्वारो मोराटा तो मुकाबले के लिए चुनी गईटीम का भी हिस्सा नहीं थे। चेल्सी ने अधिक समय तक गेंद अपने नियंत्रण में रखी लेकिन मैच का पहला और एकमात्र गोल मेजबान टीम ने किया। 26वें मिनट रैफरी ने वीएआर की मदद से टोटेनहम को पेनाल्टी दी जिसे गोल में बदलकर इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने मेजबान टीम को दूसरे लेग से पहले महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी। पहले हाफ में चेल्सी दो बार गोल करने के करीब पहुंची लेकिन गेंद गोलपोस्ट से टकराकर बाहर चली गई। मिडफील्डर एंगोलो कान्ते और युवा विंगर केलम हसन-ओदोई अपनी टीम के लिए गोल नहीं दाग पाए। दूसरा हाफ भी रोमांचक रहा और चेल्सी के डिफेंडर आंद्रेस क्रिस्टेनसन को बराबरी का गोल करने का एक बेहतरीन मौका मिला। हालांकि, वह अपनी टीम की हार नहीं टाल सके।

संक्षिप्त समाचार

चेतेश्वर पुजारा ने युवाओं के लिए 'बेंचमार्क' तय कर दिया है : गिल

कोलकाता। शुभमान गिल को भारत के भविष्य के खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है और चेतेश्वर पुजारा की आस्ट्रेलिया में खेली गयी मैराथन पारी से प्रेरित पंजाब के सलामी बल्लेबाज ने कहा कि भारतीय टीम के इस खिलाड़ी ने युवाओं के लिए 'बेंचमार्क' तय कर दिया है। गिल ने रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप बी मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''ऐसे बहुत कम बल्लेबाज हैं जो पूरे दिन बल्लेबाजी कर सकते हैं और इतनी गेंदों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने (पुजारा) ने एक दौरे पर 1200 से ज्यादा गेंद खेलीं जो सचमुच बेहतरीन है। दौरे पर 500 रन बनाना संभव दिख सकता है। लेकिन इतनी सारी गेंदों का सामना करना युवाओं के लिए 'बेंचमार्क' तय करता है।'' उन्होंने कहा, ''चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखते हुए काफी कुछ सीखा जा सकता है, वह क्रीज पर कितने धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं। आस्ट्रेलिया के पास विश्व स्तरीय गेंदबाज थे और उनके खिलाफ इतनी मुश्किल पिचों पर रन बनाना शानदार है। मुझे उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद है जबकि आजकल बल्लेबाज तेजी से रन जुटाने की कोशिश में रहते हैं। ''

किक मारते ही अपनी टांग तुड़वा बैठा एमएमए फाइटर किंग

जालन्धर । अमरीकी एमएमए फाइटर जोनाथन किंग के साथ बीते दिन बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल उनका क्रिस विलियम्स के साथ मुकाबला जहां वह पहले ही राऊंड में अपनी टांग तुड़वा बैठे। हुआ यूं कि पहले ही राऊंड में जोनाथन क्रिस पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में उन्होंने क्रिस की टांग पर किक मारकर उसे गिराना चाहा। लेकिन हो गया बिल्कुल ऊलट। किक के कारण जोनाथन की ही टांग की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कहा है कि जोनाथन को हड्डी ठीक होने के लिए कम से कम एक साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

ऑस्ट्रेलिया की घर में हार : फिंच, हैंड्सकोंब, मिशेल मार्श हुए टीम से बाहर

मेलबोर्न । भारत से टेस्ट सीरीज हारने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने आरोन फिंच, हैंड्सकोंब और मिशेल मार्श को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलने के बाद 24 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऐसे में इन तीनों क्रिकेटरों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 13 सदस्यी टीम से बाहर कर दिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेगी। ह्यूद्ध, विक्टोरिया के 20 वर्षीय बल्लेबाज विल पुकोवस्की को अंतरराष्ट्रीय टीम में पदार्पण के लिए बुलाया गया है, अक्टूबर में वेस्टर्न आस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 243 रन बनाए थे, हालांकि 6 सप्ताह बाद उन्होंने मानसिक बीमारी के चलते क्रिकेट से अवकाश ले लिया था। मैट रेनशॉ और जो बर्न्स को भी आस्ट्रेलियाई टीम में वापिस बुलाया गया है। रेनशॉ ने आखिरी बार मार्च-अप्रैल में जोहानसबर्ग में अपना 11वां टेस्ट खेला था। उन्हें केपटाउन टेस्ट में बॉल टेम्परिंग प्रकरण के बाद आखिरी क्षणों में बुलाया गया था। अन्य खिलाड़ी बर्न्स भी अच्छी फार्म में खेल रहे हैं और शैफील्ड शील्ड में 472 रन के साथ पांचवें शीर्ष स्कोरर हैं। 29 वर्षीय बल्लेबाज के नाम 14 मैचों में 3 टेस्ट शतक हैं और रिकी पोंटिंग के पसंदीदा खिलाड़ियों में है। सभी 3 बल्लेबाज टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका के खिलाफ होबार्ट में 17 जनवरी से होने वाले 3 दिवसीय अभ्यास मैच में गुलाबी गेंद से खेलेंगे। तीसरे नंबर के मार्नस लाबुसचांगे को भी अभ्यास मैच के लिए अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय चयनकर्ता प्रमुख ट्रेवर होंस- आखिरकार पीटर, आरोन, शॉन और मिशेल टेस्ट स्तर का वह प्रदर्शन नहीं दिखा सके जिसकी हमने उनसे उम्मीद की थी। सभी चार खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और उनके लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं।

धन की कमी के कारण ओलंपिक क्वालीफायर से हट सकता है पाकिस्तान

कराची।

धन की कमी से जूझ रही पाकिस्तान हाकी महासंघ (पीएचएफ) एफआईएच प्रो हाकी लीग से हटने पर विचार कर रहा है जो 2020 ओलंपिक खेलों का क्वालीफाइंग टूर्नामेंट है। पाकिस्तान की टीम पर इससे पहले भारत में पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए विश्व कप में धन की कमी के कारण भाग नहीं लेने का खतरा मंडरा रहा था। पाकिस्तान को प्रो हाकी लीग के पहले चरण के मैच को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में दो फरवरी को खेलना है। इसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करना है। पाकिस्तान को इसके दूसरे चरण के मैचों के लिए यूरोप का दौरा करना है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि पीएचएफ धन की कमी के कारण प्रो-लीग से हटने पर विचार कर रहा था और इससे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पाकिस्तान को दो साल का निलंबन झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, '' पीएचएफ ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले पहले चरण के मैचों के लिए लाहौर में अभ्यास शिविर लगाया है। इसके लिए 45 खिलाड़ियों को बुलाया गया है लेकिन उनके दौरे के खर्च का इंतजाम अब तक नहीं हो सका है।'' पाकिस्तान हाकी टीम को पहले चरण के दौरे में लिए ढाई करोड़पाकिस्तान हाकी टीम को पहले चरण के दौरे में लिए ढाई करोड़ और यूरोप में होने वाले दूसरे दौर के लिए लगभग सात करोड़ रूपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, '' पीएचएफ ने धन के लिए सरकार से संपर्क किया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। ऐसा ही भारत में हुए विश्व कप के समय हुआ था

पाकिस्तान टीम का बिगड़ा माहौल, सरफराज के बयान से नाराज हुए गेंदबाज

कराची।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को साउथ अफ्रीका से मिली दूसरे टेस्ट में हार सताई जा रही है। आलम यह कि उन्होंने सिर्फ गेंदबाजों को ही इसका कसूरवार ठहराया। सरफराज ने मैच के बाद जो जो बयान दिया था उसके बाद टीम के गेंदबाज नाराज हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, टीम का माहौल भी बिगड़ता नजर आ रहा है। सरफराज ने अपने पेसर्स की ये कहकर आलोचना की थी कि उन्होंने आशानुरूप प्रदर्शन नहीं किया था। सरफराज ने कहा कि तेज गेंदबाजोंने पहले टेस्ट में कहीं अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के तेज गेंदबाजों ने अपने कप्तान की आलोचना के प्रति नाराजगी जताई है। केपटाउन टेस्ट के दौरान खासतौर पर पाकिस्तानी स्पीडस्टार मोहम्मद आमिर के प्रदर्शन में खासा गिरावट आई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर ने इस मैच में अपनी 61 फीसदी गेंदें 120-132 किमी/घंटे की रफ्तार से ही फेंकी जबकि उनकी औसत स्पीड ही 140 किमी/घंटे की है। ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान के कुछ और गेंदबाजों की भी रही, जबकि दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने पूरी लय में गेंदबाजी की थी। सरफराज ने मैच के बाद कहा, अगर आप हमारी गेंदबाजी और उनकी गेंदबाजी के बारे में बात करें, तो मेरे ख्याल से दोनों में अंतर है। जिस तरह हमारे गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं वह टेस्ट मैच में आशा के अनुरूप नहीं है। अगर आप हमारे गेंदबाजों के देखें तो वे 128-129 किमी/घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी औसत स्पीड 130किमी/घंटे है जबकि उनके गेंदबाज 145 किमी/घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आप यहां इतनी कम गति से गेंदबाजी करेंगे तो आपको विकेट नहीं मिलेंगे। जियो टीवी के मुताबिक टीम सूत्रों के अनुसार, ' आलोचनाओं से गेंदबाज काफी निराश हैं वे योंकि कहा जा रहा है उनकी बदौलत पाक टीम को मौजूदा सीरीज में अब तक कोई जीत नहीं मिली है।

WBBL में फिर चला स्मृति का बल्ला, 200 की स्ट्राइक रेट से लगाई फिफ्टी

जालन्धर ।

भारतीय वुमैंस क्रिकेट टीम की नई सनसनी स्मृति मंधाना ने वुमैंस बिग बैश लीग में एक बार फिर से अपने बल्ले का जौहर दिखाया है। स्मृति ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ बीते दिनों हुए मैच में महज 25 गेंदों में 52 रन की धमाकेदार पारी खेली। स्मृति ने तेजतर्रार पारी के दौरान 7 चौके तो 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। स्मृति ऐसे समय में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने उतरी थी जब उनके सामने 20 ओवरों में 189 रनों का भारी भरकम लक्ष्य था। स्मृति अपनी खेली शानदार पारी के दौरान इतनी दक्ष दिख रही थी कि उन्होंने महज 6 ओवरों में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर ली। बड़ी बात यह रही कि स्मृति का साथ देने आई ईजी फजैकेर्ले (4), एस. दफरा (0) जल्दी ही आऊट हो गई। लेकिन एक छोर संभाले स्मृति ने आतिशी पारी खेलनी जारी रखी। स्मृति के आऊट होने के बाद रैडमायने ने 54 रन बनाकर मैच टाई करवा दिया। मैच सुपरओवर में पहुंचा तो स्मृति ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे दिखा दिए। लेकिन इसके बाद वह बड़ी हिट लगा नहीं पाई। लिहायजा उनकी टीम मैच गंवा बैठी। बता दें कि स्मृति को अभी कुछ दिन पहले ही रेचेल हेयोइ फ्लिंट पुरस्कार से आईसीसी सम्मानित कर चुकी है। स्मृति आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे प्लेयर का भी खिताब जीत चुकी हैं। उन्हें आईसीसी ने 2018 की अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे और टी-20 टीम में भी जगह दी थी। स्मृति अब तक 12 वनडे मैचों में 66.90 की स्ट्राइक रेट से 669 तो 25 टी-20 में 130.67 की स्ट्राइक रेट से 622 रन बना चुकी हैं।

खेलो इंडिया के जरिए डोपिंग रोधी कार्यक्रम चलाएगी नाडा

पुणे ।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) यहां जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2019 के जरिए देश भर में डोपिंग रोधी कार्यक्रम चलाकर खिलाड़ी के बीच जागरुकता फैलाएगी। यह कार्यक्रम करीब 6000 खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाएगा। नाडा ने महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने बुधवार को यहां डोपिंग रोधी कार्यक्रम के दौरान कहा, हम जानते हैं कि यह डोपिंग को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए यह सबसे अच्छा मंच है क्योंकि यहां भारत के सबसे अच्छे युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भविष्य में इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले वर्ष दिल्ली में खेलो इंडिया के दौरान करीब 12 खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के कारण जांच के दौरान पॉजिटिव पाए गए थे और इसलिए हम यहां हर खिलाड़ी तक पहुंच रहे हैं।अग्रवाल ने कहा कि नाडा ने अपनी वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा जारी की गई प्रतिबंधित दवाओं की सूची मुहैया कराने के अलावा खिलाड़ियों की मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है। पिछले दो दिनों में इस कार्यक्रम के जरिए 700 से अधिक खिलाड़ियों को जानकारी दी जा चुकी है। नाडा ने अब तक 19 आउट ऑफ कम्पटीशन सैम्पल एकत्रित किए हैं और 20 जनवरी तक चलने वाले इन खेलों के दौरान कई और टेस्ट किए जाएंगे। बीते साल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दौरान नाडा ने 377 सैम्पल जमा किए थे।

श्रीकांत ने बेंगलुरु को मुंबई पर दिलाई जीत

बेंगलुरु।

स्टार खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने मंगलवार को यहां श्री कांतीरवा स्टेडियम में वोडाफोन प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) के चौथे सीजन के मैच में मुंबई रॉकेट्स के खिलाफ बेंगलुरू रैपटर्स को 4-0 से आगे कर मेजबान टीम को जीत दिला दी। मुकाबले में हालांकि दो मैच बाकी हैं लेकिन उनके परिणाम बेंगलुरू की जीत को टाल नहीं पाएंगे। पहला मैच महिला एकल वर्ग का था। इस मैच में बेंगलुरू की वू थी थ्रांग का सामना मुंबई की श्रेयांशी परदेशी से था जहां मुंबई की खिलाड़ी को वू ने 15-4, 11-15, 15-7 से हरा दिया। परदेशी ने हालांकि पहला गेम आसानी से गंवाने के बाद दूसरे गेम में वू को अच्छी टक्कर देते हुए मैच को तीसरे गेम में पहुंचा दिया, लेकिन वह अपनी फॉर्म को तीसरे गेम में जारी नहीं रख पाईं। यह बेंगलुरू का ट्रंप मैच था और इस जीत से बेंगलुरू 2-0 से आगे हो गई। मुकाबले का दूसरा मैच पुरुष युगल का था। बेंगलुरू के मोहम्मद अहसान और हेंड्रा सेतियावान की जोड़ी के सामने मुंबई ने किम जी जुंग और ली योंग डाए को उतारा था। बेंगलुरू की जोड़ी ने इस मैच में भी जीत हासिल करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। अहसान और हेंड्रा की जोड़ी ने मुंबई की किम और ली की जोड़ी को सीधे गेमों में 15-11, 15-11 से मात दी। तीसरे मैच में बेंगलुरू के स्टार खिलाड़ी श्रीकांत और मुंबई के आंद्रेस एंटनसन पुरुष एकल वर्ग में उतरे। श्रीकांत ने कड़े मुकाबले में आंद्रेस को 15-14, 15-13 से परास्त कर बेंगलुरू को जीत दिलाई। श्रीकांत ने 5-5 के स्कोर के बाद 9-7 की बढ़त ली जिसे आंद्रेस ने लगातार तीन अंक लेकर उतार दिया। श्रीकांत ने स्कोर तुरंत 10-10 से बराबर किया। यहां से आंद्रेस ने फिर 13-11 की बढ़त ले ली और एक बार फिर श्रीकांत ने स्कोर 14-14 से बराबरी पर पहुंचा दिया। लेकिन श्रीकांत एक अहम अंक लेकर गेम अपने नाम कर गए। दूसरे गेम में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। आंद्रेस ने 2-0 की बढ़त ली जिसे श्रीकांत ने बराबर कर दिया। यहां से आंख मिचौली का खेल जारी हो गया। कभी श्रीकांत आगे होते तो आंद्रेस बराबरी कर लेते। तो कभी आंद्रेस आगे होते तो श्रीकांत बराबरी कर लेते। स्कोर 3-3, 4-4 से होता हुआ 13-13 तक गया और यहां श्रीकांत ने लगातार दो अंक लेकर अपना मैच भी जीता और बेंगलुरू को भी जीत दिलाई।

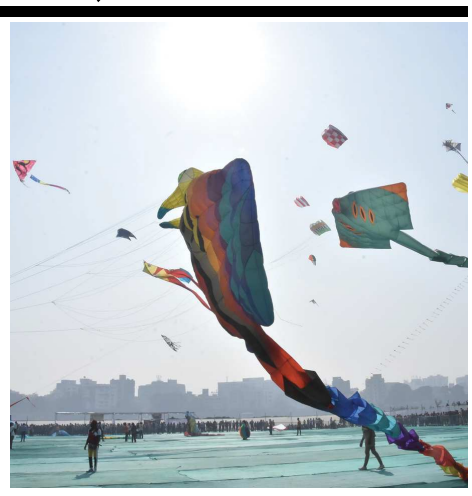

सूरत। पतंग महोत्सव 2019 सरिता सागर अडाजण सूरत में रखा गया जिसमें बड़ीं संख्या में शहर वासियों के साथ-साथ नेताओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महोत्सव के दौरान शहर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा सा नजर आया। इस महोत्सव में देश से ही नहीं बल्की विदेश से सैलानी हिस्सा लेने आते है।

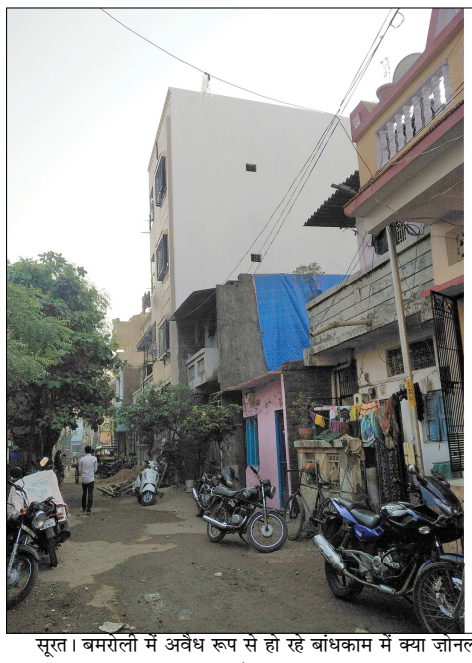

सूरत। बुधवार को दिन भर एस.एम.सी द्वारा कतारगाम जोन में आवारा घुमने वाले पशुओं को पकड़ा गया जिसमें बड़ीं संख्या में वे गाय थी जो दुध पीने के बाद उनके मालिकों द्वारा आवारा धुमने के लिए छोड़ दी जाती है। जिससे रोड़ पर आए दिन दुर्घटनाएं सामने आती रहती है।

सूरत। बमरोली में अवैध रूप से हो रहे बांधकाम में क्या ज़ोनल ऑफीसर की नजर हैं की नही कोई भी इमरजेंसी वाहन- व्यहार के आने जाने तक की जगह भी नही हैं,इस लिये जवाबदार कोन? अधिकारी के पदाधिकारी ।

महिला से छेड़छाड़ के आरोप में कांग्रेस नेता गिफ्तार

भरुच। अंक्लेश्वर निवासी एक महिला की शिकायत के आधार पुलिस ने अंक्लेश्वर शहर कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। जानकारी के मुताबिक भरुच जिले के अंक्लेश्वर निवासी एक महिला तहसील कचहरी पर अपने बच्चों के आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के सिलसिले में गई थी। जहां एक एजन्ट से फार्म भरवा रही थी, तब अंक्लेश्वर शहर कांग्रेस प्रमुख नूर महमद उर्फ नुरूभाई अहमद कुरैशी ने महिला का हाथ पकड़ लिया और उससे मोबाइल नंबर मांगा। अचानक घटी इस घटना से हतप्रभ महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में महिला ने अंक्लेश्वर पुलिस थाने में नूर महमद कुरैशी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवा दी। जिसके आधार पर पुलिस ने चंद घंटों में नूर महमद कुरैशी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है।

भानुशाली के हत्यारे भचाऊ या सामखियाली से ट्रेन में चढ़ा होने की आशंका

अहमदाबाद। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की हत्या करनेवाले अज्ञात बदमाश भचाऊ या सामखियाली रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़े होने की आशंका है। पूर्व विधायक की हत्या के बाद रेलवे सुरक्षा की कमजोरी सामने आई है। भचाऊ और सामखियाली स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की सुविधा नहीं है। जबकि इन दोनों स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है। ऐसे में सीसीटीवी नहीं होने से आपराधिक तत्त्वों को खुला मैदान मिल जाता है। स्टेशन पर कोच इंडिकेटर भी नहीं लगे। रेल प्रशासन की इस घोर लापरवाही का फायदा उठाकर जयंती भानुशाली के हत्यारे भचाऊ और सामखियाली रेलवे स्टेशन से सयाजीनगरी एक्सप्रेस में चढ़े होने की आशंका है।

गोवा, दिल्ली, हरिद्वार और चंडीगढ़ तक रोडवेज की बसें चलाने की योजना

सूरत। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की अब अहमदाबाद से गोवा, दिल्ली, हरिद्वार और चंडीगढ़ तक बसें चलाने की योजना है। जिसके लिए संबंधित राज्यों से एनओसी मिलते ही अहम दाबाद से इंटरस्टेट बस सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच रोडवेज की बसें चल रही है। लेकिन अब गुजरात ने अन्य राज्यों के बीच बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। राज्य परिवहन निगम ने अन्य राज्य स्थित पर्यटन स्थलों के साथ साथ गुजरात का व्यापार दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से इन इन रूट पर बसें चलाने का फैसला किया है। हांलाकि इन रूट पर बसें चलाने के लिए संबंधित राज्यों से एनओसी लेना जरूरी है, जिसके लिए गुजरात परिवहन के अधिकारियों को गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ की विजिट करने का आदेश दिया गया है। एनओसी मिलने के बाद अहमदाबाद से वडोदरा और सूरत से गोवा की बसें शुरू की जाएंगी। अहमदाबाद से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच

भी गुजरात परिवहन निगम की बसें दौड़ाई जाएंगी। जिसमें ट्राफिक मिलने पर ऐसी बसें वडोदरा और सूरत भी शुरू की जा सकती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ के ज्यादा यात्री मिलने पर बस सेवा अन्य कई स्थलों पर भी उपलब्ध होगी। गुजरात परिवहन निगम अपनी बसों की संया बढ़ा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में 2160 नई बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी, जिसका यात्रियों को फायदा मिलेगा। अहमदाबाद को 300 से 350 जितने बसें मिलने की संभावना है। वर्तमान में अहमदाबाद से गुजरातभर में चलनेवाली 125 जितने बसों के किलोमीटर पूर्ण हो चुके हैं। ऐसी बसों को हटाकर निगम की नई बसें लाने की योजना है। नई बसों के आने पर नए रूट भी शुरू किए जाएंगे।

पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फूटेज लिए

भानूशाली की हत्या की घटना का पुलिस ने रिकन्स्ट्रक्शन किया

हत्या के एक सिर्फ गवाह पवन मोरे की तीन से चार घंटे तक पूछताछ : हत्यारा का स्केच तैयार किया जाएगा

अहमदाबाद। भाजपा के नेता जयंती भानूशाली की हत्या के ३६ घंटे बाद पुलिस ने एच १ कोच में घटना का रिकन्स्ट्रक्शन किया गया। डीवायएसपी स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति में कौन-सी स्थिति में उनको गोली मारी गई यह जानने के लिए पुलिस ने प्रयास किया। पुलिस ने बुधवार को ट्रेन के कोच में डॉग स्कवोड, एफएसएल सहित की टीमों को साथ में रखकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने हत्या के एक सिर्फ गवाह पवन मोरे की पूछताछ और उसने किए व्यवहार के आधार पर हत्यारा का स्केच तैयार करने की दिशा में जांच शुरू की गई है। पुलिस की जांच टीम के अधिकारियों ने बुधवार को जांच के दौरान ट्रेन के दो टिकट चेकर, ३ एटेन्डन्ट और हत्या का गवाह पवन मोरे को साथ में रखा गया। बेलास्टिक रिपोर्ट के आधार पर कितनी दूरी से गोली मारी गई थी इसकी कडी पुलिस को मिल गई है। पुलिस की टीम ने जयंती भानूशाली की हत्या के पहले ट्रेन कहां-कहां रूकी थी तथा निकट के रेलवे स्टेशन सहित के स्थलों की सीसीटीवी फूटेज लेकर इसके आधार पर हत्यारे की कोई कडी मिल जाए इसके लिए प्रयास शुरू किया गया है। हालांकि, अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जयंती भानूशाली के साथ कोच में यात्रा करने वाले पवन मोरे ने आरोपी को देखा यह पुलिस को जानकारी मिली है। हत्या के एक सिर्फ गवाह पवन मोरे की पूछताछ और उसने किए व्यवहार के आधार पर हत्यारा का स्केच तैयार करने की दिशा में जांच शुरू की गई है। पुलिस की जांच टीम के अधिकारियों ने बुधवार को जांच के दौरान ट्रेन के दो टिकट चेकर, ३ एटेन्डन्ट और हत्या का गवाह पवन मोरे को साथ में रखा गया। फिलहाल पुलिस द्वारा स्केच आर्टिस्ट की मदद से पवन के व्यवहार के आधार पर हत्यारा का स्केच बनाने का प्रयास कर रही है। पुलिस द्वारा यह पूरे मामले में पवन मोरे ही सिर्फ एक गवाह होने की बात की वजह से इसकी बुधवार को तीन से चार घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। जबकि ट्रेन की चेन पुलिंग हुई तब ड्राइवर और गार्ड द्वारा किसे जानकारी दी गई और रेलवे के किस अधिकारी क्या काम किया गया यह जानकारियों को लेने के लिए प्रयास तेज किया गया है। सीट की जांच में शहर क्राइमब्रांच, एटीएस और सीआईडी क्राइम तथा रेलवे पुलिस के अधिकारियों की टीमें शामिल हुई और पूरे मामले में उनकी कडी लेने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं।

भाजपा के नेता भानूशाली के अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया। इसके पहले उनकी अंतिमयात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

BRTS की बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर सवाल उठे

BRTS के कोरिडोर के ४०० चार रास्ते-सर्कल खतरनाक

अहमदाबाद। शहर के विभिन्न क्षेत्र में बीआरटीएस बस द्वारा वाहनचालकों को टक्कर मारने और इसकी वजह से निर्दोष लोगों की मौत होने के हाल में सामने आई घटनाओं के बाद अब बीआरटीएस बस की सेवा और इसके ड्राइवरों की वाहन चलाने की पद्धति और क्षमता को लेकर गंभीर सवाल उठाये गये है। दूसरी तरफ, शहर में बीआरटीएस की कोरिडोर के ४०० चाररास्ते और सर्कल काफी खतरनाक सबसे ज्यादा रिस्की है, जिसकी वजह से यह स्थलों या पॉइंट पर एएमसी दुर्घटना निराकरण कदम या तो बम्प, निशान सहित के कदम उठाये जाए ऐसी मांग नागरिकों ने की है। एएमसी शासकों ने भी हाल में एक के बाद एक बीआरटीएस बस की दो जानलेवा दुर्घटना करने वाले निजी ऑपरेटर चार्टर्ड स्पीड को पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाकर अब स्पीड लिमिट तय रखने की दिशा में तथा ड्राइवरों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आरटीओ से वासणा के चंद्रनगर के बीच वर्ष २००९ में शहर की प्रथम बीआरटीएस बस सर्विस शुरू की गई थी। हालांकि, पिछले कई दिनों से एएमटीएस की लाल बस के जैसे अब बीआरटीएस बस भी नागरिकों के जानमाल के लिए घातक बन गई है। एएमसी प्रशासन द्वारा प्रिय ऑपरेटर को बचाने की नीति अपनाई गई होने से बीआरटीएस कोरिडोर के ४०० चाररास्ते या सर्कल वाहनचालकों के लिए काफी खतरनाक बन चुके हैं। इस दौरान एक के बाद एक दो दुर्घटना करने वाले बस के ऑपरेटर चार्टर्ड स्पीड को १० लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन द्वारा बीआरटीएस सर्विस में रोजाना की कुल २५५ बस चलाई जा रही है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)